1	2	3
अरहर	315.6	464.4
मूंग	420.8	728.8
मसूर	504.4	738.0
उड़द	382.3	554.0
आलू	169.7	158.3
प्याज	344.8	437.8
दूध	283.2	392.8
मछली	511.6	627.1
गोश्त	533.5	666.3
चाय	390.2	468.4
लाल मिर्च	192.0	461.4
साफ्ट कोक	606.3	606.3
मिट्टी का तेल	403.5	410.4
साबुन	325.9	466.2
आटा	232.5	353.5
चीनी	303.8	337.8
गुड़	412.6	427.2
वनस्पति	325.1	451.6
मूंगफली का तेल	316.6	384.4
सरसों का तेल	246.2	344.3
नारियल का तेल	238.9	439.6
जिंजली का तेल	276.1	363.2
नमक	233.9	254.3
दियासलाई	129.0	129.0
सूती कपड़ा (मिल का)	271.9	291.4
समग्र वस्तुएं	358.9	439.0

रेगिस्तान विकास योजना का असफल होना

2795. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1988 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डैजर्ट डेवलपमेंट प्लान ए फेलियर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने तथ्यों का पता लगाया है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के विफल रहने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 9 दिसम्बर, 1988 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "डैजर्ट डेवलपमेंट प्लान ए फैलियर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की मरु भूमि विकास कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट पर आधारित है।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह कार्यक्रम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकने में इन कारणों से अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सका है, जैसे एक बड़े क्षेत्र के लिए सीमित संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा वितरण, माइक्रो, वाटरशेड पर आधारित आयोजना और योजनाओं के निष्पादन का अभाव जसी आयोजना और कार्यान्वयन की कमियां, कमजोर आंकड़ा आधार, कार्यक्रम को ठीक प्रकार से क्रमबद्ध नहीं किया जाना और सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख रखाव के लिए अपर्याप्त प्रबन्ध, सृजित परिसम्पत्तियों का पूरा उपयोग न किया जाना आदि। राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी के लिए उचित संस्थागत प्रबन्धों की भी कमी रही थी।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा समय-समय पर की गई कार्यक्रम की विभिन्न समीक्षाओं में पहले से ध्यान में रखा गया है। सरकार ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जल संसाधन संरक्षण और एकत्रीकरण, भूमि विकास और नमी संरक्षण, वनरोपण, चरागाह तथा घास वाली भूमि के विकास आदि योजनाओं के जरिए मरुस्थलीकरण को रोकने के बारे में इस कार्यक्रम में विशेष ध्यान देकर पहले ही उपचारात्मक उपाय शुरू कर दिए हैं। विभिन्न मुख्य क्षेत्रों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक निधियों के आवंटन को निर्धारित करने पर बल दिया गया है जिसमें उन योजनाओं पर विशेष बल देने को कहा गया हैं जो मरुस्थलीकरण के दबाव को कम करने में सीधे तौर पर सहयोग देती हों। स्थापना और प्रशासन खर्च को वार्षिक आवंटन के 18 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया गया है ताकि विकास कार्यों के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध हो सकें। अब कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए प्रत्येक खण्ड में कुछ सघन क्षेत्रों के समन्वित विकास पर बल दिया जाता है ताकि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला जा सके।

वर्ष के दौरान निधियों की रिलीज अपेक्षित वित्तीय प्रगति को पूरा करने पर की जाती है। निगरानी की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पहले ही कार्यक्रम का विस्तृत मूल्यांकन शुरू कर दिया है, यद्यपि डा०वाई०के० अलाघ, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति इस कार्यक्रम का विस्तृत मूल्यांकन कर रही है, उनकी रिपोर्ट कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी में और सुधार करने के लिए मार्गदर्शन करेंगी।

Construction of Ruhiyan Tank Project

2796. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHIL BARONGPA:; SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Fertiliser is making funds available for the construction of Ruhiyai tank project in Guna District for providing water to fertilizer plant at Vijaypur, if so, what is the amount of funds made available by Central Government to Government of Madhya Pradesh till March, 1988, during 1988-1989 and for the year 1989-90; and

(b) what is the quantity of water proposed to be supplied to the plant, what is the expenditure incurred on the project so far up to (a) March, 1988 (b) during the year 1988-89; when this project started and what is the target date of its completion, by what date the water is likeiy to be made available to the fertiliser plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILI-